पूर्वी दिल्ली के घरेलू गैस वितरकों ने पिछले चार महीनों से उन उपभोक्ताओं को नए एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी है जिन्होंने वितरकों के पास घरेलू गैस के नये कनेक्शनों के लिये पंजीकरण कराया था और जिन्हें गैस कनेक्शन जारी करने के लिये वितरकों द्वारा पत्र भी डाल दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन नियमों के अधीन नये एल. पी. जी. कनेक्शनों जारी नहीं किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शपथ पत्रों के आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शनों का आवंटन

96. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 24 नवम्बर, 1986 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न 1789 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा न्यायिकोत्तर स्टाम्प पेपरों पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करके इनके आधार पर जारी किये गये गैस कनेक्शनों की जांच की जाये तो इस प्रकार लिये गये लगभग 80 प्रतिशत कनेक्शन जाली पाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी कनेक्शनों की वास्तविकता का पता लगाने का विचार रखती है अथवा क्या इस संबंध में कोई विसंगति सरकार के ध्यान में आई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) नये कनेक्शन रिलीज करते समय शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, टर्मिनेशन वाउचर के गुम होने पर डिस्ट्रीब्यूटर केवल शपथ पत्र के आधार पर नया कनेक्शन भी तब देता है जब वह पिछले डिस्ट्रीब्यूटर से टर्मिनेशन वाउचर जारी किये जाने के बारे में पुष्टि कर लेता है।

Requirement of cement

97. SHRIMATI SUDHA VIJAY -JOSHI: Will the Minister Of INDUSTRY be pleased to state;

(a) the annual requirement of cement in the country;

(b) the estimated annual production of cement in the country during the current year;

(c) whether three will be a shortfall or excess in production; and

(d) whether distribution and sale of cement is proposed to be de-controlled totally?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The Working Group on Cement Industry in its Report of July, 1984 had estimated a demand for the year 1987-88 at 44.24 million tonnes. However, of late, the industry has been reporting sluggishness in the demand. For the current year the cement production target of 42.5 million tonnes has been fixed which is likely to be achieved. Hence, no shortfall in production during the current year is expected.

(d) There is no proposal to totally de-control the distribution and sale of cement in the country in the near future.